

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1657  
10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारंपरिक वस्त्र एकक

1657. श्री दामोदर अग्रवाल:

श्री तापिर गाव:

श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

श्री अनुराग शर्मा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का लाभ उठाते हुए विशेषकर झांसी और ललितपुर सहित बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्पादन संकुलों को लाभ पहुंचाने हेतु संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे उभरते बाजारों में निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्यनीति बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यनीति का ब्यौरा क्या है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा पारंपरिक वस्त्र इकाइयों के लिए उत्पाद विविधीकरण, बाजार-विशिष्ट प्रोत्साहन, व्यापार सुगमता उपाय और क्षमता निर्माण पहलें क्या हैं;
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में झांसी और ललितपुर जिलों सहित बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्पादन संकुलों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय हरित और पर्यावरण सतत मानकों का अनुपालन करने में भारतीय वस्त्र निर्यातकों की सहायता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, जल का बेहतर प्रसंस्करण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रमाणन लागतों के लिए सहायता सहित क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) क्या उक्त एफटीए के अंतर्गत पिछड़े और आकांक्षी जिलों के छोटे निर्यातकों और बुनकरों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिए कोई लक्षित सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है या कोई मार्गदर्शन तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग पर अमेरिकी प्रशुल्क के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए), जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सभी उत्पादों पर अपने टैरिफ को समाप्त कर दिया, जो 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ। भारत-यूई (संयुक्त अरब अमीरात) सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता), 1 मई 2022 से लागू किया गया है, अधिकांश लाइनों को अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करता है। वर्ष 2024-25 में यूई को भारत के वस्त्र और अपैरल (हस्तशिल्प सहित) का निर्यात 2156.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वर्ष 2023-24 में 2019.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 6.8% की वृद्धि दर्शाता है और वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत के वस्त्र और अपैरल (हस्तशिल्प सहित) का निर्यात 732.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वर्ष 2023-24 में 659.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10.9% की वृद्धि दर्शाता है। झांसी और ललितपुर जिलों सहित बुंदेलखंड क्षेत्र ने उक्त अवधि में हस्तशिल्प सहित वैश्विक वस्त्र और अपैरल में वृद्धि प्रदर्शित की है।

(ख) से (ङ): सरकार भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों का क्रियान्वयन कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक,

एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करने के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर फोकस करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित, रोजगार उन्मुखी, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र के लिए एंड टू एंड सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल है। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। सरकार परिधान/गारमेन्ट्स और मेड-अप के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) और अन्य वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना नामक दो छूट योजनाओं का भी संचालन कर रही है।

मंत्रालय ने उद्योग के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कार्य बल का गठन किया है ताकि सतत उत्पादन मॉडल अपनाने में वर्तमान स्थिति और समस्याओं का पता लगाया जा सके। सरकार, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक/वनस्पति रंगों के प्रचार और डार्ई हाउस की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने पर्यावरण पर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के साथ उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) पहल की शुरुआत की है।

वस्त्र उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने और विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मौजूदा प्रसंस्करण क्लस्टरों के साथ नए प्रसंस्करण पार्कों में नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन को सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय 12वें वित्त वर्ष से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय ने कुछ संशोधनों के साथ उक्त योजना को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। पीआईबी ने 275 करोड़ रुपये के परिव्यय से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना को मंजूरी दी है।

सरकार लगभग 20 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र सहित क्लस्टरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक मेगा क्लस्टर परियोजना को लागू कर रही है। यह परियोजना बुंदेलखंड के सभी 07 जिलों में फैली हुई है, जिससे 2,000 से अधिक कारीगर लाभान्वित होंगे। सरकार विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनके प्रभावी एकीकरण के लिए पिछड़े और महत्वाकांक्षी जिलों में छोटे निर्यातकों और बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन और समर्पित हैंड होल्डिंग तंत्र भी प्रदान कर रही है। हथकरघा के निर्यात संवर्धन के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर हथकरघा निर्यातकों/बुनकरों की भागीदारी, जिसमें छोटे निर्यातकों, पिछड़े और आकांक्षी जिलों के बुनकर शामिल हैं, को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों/मेलों, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, क्रेता विक्रेता बैठक, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक, बिग टिकट कार्यक्रम, भारत टेक्स में शामिल किया जाता है, जिन्हें हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

**(च):** मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य देशों को हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान के भारत के निर्यात की मॉनीटरिंग कर रहा है। मंत्रालय भारत के वस्त्र और अपैरल निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव और अन्य चुनौतियों का आकलन करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित निर्यातकों के साथ नियमित परामर्श करता है। जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान, विश्व में वस्त्र और अपैरल (हस्तशिल्प सहित) का भारत का कुल निर्यात 37.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे वैश्विक चुनौतियों के बीच उतार-चढ़ाव परिलक्षित होते हैं।

\*\*\*